

इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण की संभावनाओं को उजागर करना

यह एडिटरियल 28/06/2023 को 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Electronic manufacturing in India needs rapid charging”](#) लेख पर आधारित है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर और नरियात-उन्मुख बनने की संभावनाओं तथा इससे संबंध चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलम्ब के लिये:

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण और आईटी हार्डवेयर के लिये PIL योजनाएँ, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के वनिर्माण संवर्धन की योजना (SPECS), संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण कलस्टर योजना (EMC 2.0), भारत का सेमीकंडक्टर मशिन, मेक इन इंडिया

मेन्स के लिये:

भारत एक इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण केंद्र के रूप में - संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र।

वशिव की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत ने स्वयं को गतिशील कर लिया है। इस संदर्भ में, [इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण](#) के क्षेत्र में प्रगतिका अपना वशिष महत्त्व है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिये [भारत सरकार](#) ने [भारतीय बाज़ार को अपने अगले इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण गंतव्य के रूप में देखने लगी है।](#)

इस क्षेत्र की विकास क्षमता और बड़े पैमाने पर रोज़गार प्रदान कर सकने की क्षमता को समझते हुए, [भारत सरकार](#) देश के वनिर्माण क्षेत्र (इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र सहित) को समर्थन और गति प्रदान करने हेतु एक प्रमुख नीति पहल के रूप में [मेक इन इंडिया](#) कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ा रही है।

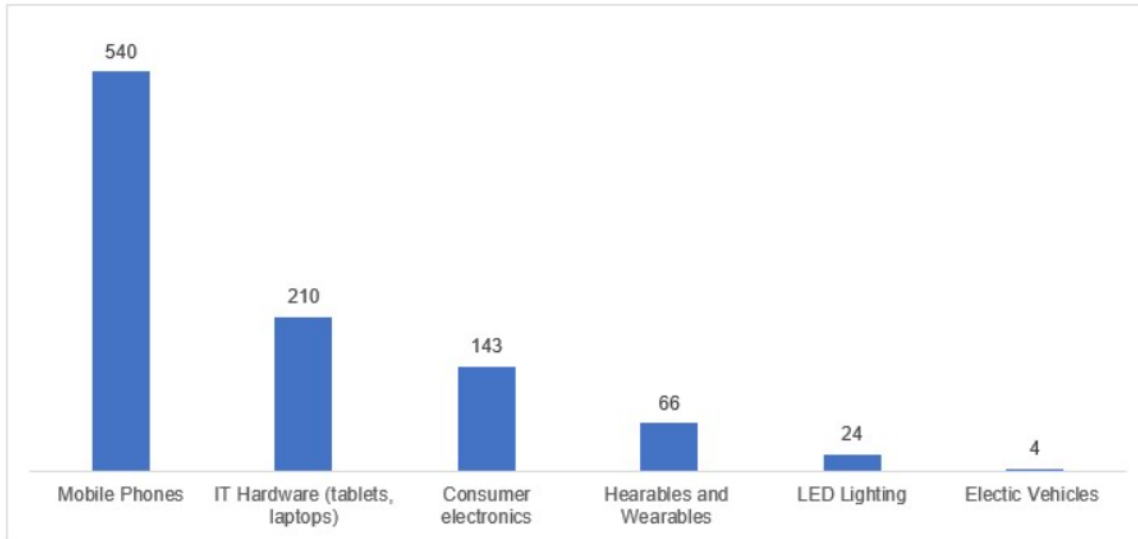
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का वर्तमान परिदृश्य

- **भारत के लिये खुलते अवसर:**
 - इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी वनिर्माण एवं कारोबारी श्रेणी (manufactured and traded category) है, जिसका मूल्य 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसमें से चीन लगभग 50% से अधिक की आपूर्ति करता है।
 - हालाँकि, चीन में बढ़ती वेतन लागत (wage cost) खरीदारों को अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने और जोखिम कम करने के लिये प्रेरित कर रही है, जो भारत के लिये एक अनुकूल अवसर पेश कर रही है।
 - भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिये वैकल्पिक समाधान के प्रमुख दावेदारों में से एक है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अगले 3-5 वर्षों में भारत शीर्ष नरियातक क्षेत्रों में से एक बनने की क्षमता है।
 - वित्त वर्ष 2026 तक भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
- **भारत का उत्पादन परिदृश्य:** भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण उद्योग वर्ष 2015-16 में 37.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 67.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हो गया और भारत इसे वर्ष 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर (घरेलू उत्पादन) तक ले जाने का लक्ष्य रखता है।
 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के वज़िन दस्तावेज़ 2.0 के अनुसार - भारत इस लक्ष्य तक पहुँच सकता है, बशर्ते कसकलगी की उच्च क्षमता वाले वशिष्ट उत्पाद खंडों को शॉर्टलस्ट किया जाए और प्रोत्साहन एवं नीतिगत उपायों के माध्यम से इसे समर्थन दिया जाए।
 - इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण के लिये 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आँकड़े तक पहुँचने के लिये 120-140 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नरियात महत्त्वपूर्ण है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण के लिये योजनाएँ:**
 - भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग' (ESDM) के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये नमिनलखिति योजनाएँ शुरू की गई हैं:
 - **उत्पादन लक्ष्य प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ—** (a) [बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण के लिये](#) और (b) [आईटी हार्डवेयर के लिये इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के वनिर्माण के संवर्धन हेतु योजना \(Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors- SPECS\)](#)

• **संशोधति इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण क्लस्टर योजना (Modified Electronics Manufacturing Clusters Scheme- EMC 2.0)**

- इसके अंतर्गत, देश में एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिकोण से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोत्साहनकारी परियोजना के साथ 'सेमीकंडक्टर मशीन' शुरू किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है, हालांकि रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 49% तक FDI की अनुमति है (जबकि 49% से अधिक के लिये सरकार की मंजूरी आवश्यक है)।

Global market share of key product segments in 2020-21 (US\$ billion)



भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स हब' में बदलने की राह की चुनौतियाँ

■ **शुल्कों का दोधारी तलवार के रूप में कार्य करना:**

- उच्च आयात शुल्क और सख्त स्थानीयकरण मानदंड प्रायः स्थानीय वनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये अधिरोपित किये जाते हैं। हालाँकि वे स्थानीय वनिर्माण सुनिश्चित करने में एक हद तक सफल होते हैं, लेकिन वे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
 - यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में विशेष रूप से सत्य है जहाँ आपूर्ति शृंखलाएँ वैश्विक स्तर पर आपस में जुड़ी हुई हैं।
- वनिर्माण के लिये उपयोग की जाने वाली मशीनरी और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में वित्तनाम एवं चीन जैसे देशों में भारत की तुलना में अधिक अनुकूल सब्सिडी संरचनाएँ हैं।

■ **घटक पारितंत्र का अभाव:**

- एक अन्य चुनौती यह है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिये आवश्यक घटकों का स्थानीय स्तर पर निर्माण करने वाली कंपनियों के एक सुदृढ़ पारितंत्र का अभाव है।
- भारत में एक पूर्ण घटक पारितंत्र (Component Ecosystem) की अनुपस्थिति में इन घटकों को आयात करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माताओं के लिये लागत और समय-सीमा (lead time) बढ़ जाती है।
 - स्थानीय वनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये (घरेलू वनिर्माताओं के योगदान सहित) एक सक्रिय नीति समर्थन का वर्तमान में अभाव प्रतीत होता है।

■ **कौशल विकास:**

- इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी है। भारत को एक वैश्विक केंद्र बनने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास और उन्नत वनिर्माण प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ एक उच्च कुशल कार्यबल विकसित करने की दशा में निवेश करने की आवश्यकता है।

■ **नियामक पर्यावरण:**

- भारत में नियामक ढाँचा एवं नौकरशाही कार्यवाही जटिल और धीमी है।
- नियमों को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही की लालफीताशाही (bureaucratic red tape) को कम करने से कारोबार सुगमता बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण के लिये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलागा।

■ **पर्यावरणीय स्थिरता/संवहनीयता:**

- इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण प्रायः इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जो पर्यावरणीय चुनौतियाँ पेश करता है।
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण हेतु अनुकूल वनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने जैसे संवहनीय अभ्यासों के प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव पर्यावरण के लिये इच्छित लाभ की तुलना में हानि ही अधिक पहुँचा सकता है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सुधार के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं?

■ 'स्केलेबिलिटी' की वृद्धि करना:

- इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण बड़े क्लस्टर में अधिक फलता-फूलता है जो अपेक्षित 'इकोनॉमिज़ ऑफ़ स्केल' प्रदान करता है। लेकिन भारत ने अपेक्षित स्केल पर अपने वनिर्माण क्लस्टर की परकिलपना नहीं की है।
 - भारत के पास नरियात को बढ़ावा देने के लिये देश भर में लगभग 400 वैश्व आर्थिक क्षेत्र (SEZs) हैं, जिनमें एक साथ रखकर भी देखें तो ये चीन के शेनज़ेन SEZ की तुलना में लगभग आधा नरियात ही करते हैं।
- भारत को देश भर में कुछ स्थानों पर वृहत और वैश्विक स्तर के इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर का नरिमाण करने पर ज़ोर देना चाहिये। उत्तर प्रदेश (नोएडा), तमिलनाडु और तेलंगाना पहले से ही अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं और यह उपयुक्त समय है कि वैश्विक स्तर के इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के नरिमाण के लिये बड़ा दांव लगाया जाए।

■ उच्च नरियात शुल्क को सीमिति करना:

- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार में उच्चि हसिसेदारी हासिल करने के लिये हमारेदृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, विशेष रूप से कराधान, श्रम कानूनों और श्रमिक आवास के मामले में।
 - भारत अब आयात-प्रतस्थापन इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था (import-substitution electronics economy) से नरियात-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है।
- जटिल शुल्क संरचना (उच्च और लगातार बदलती दरों के साथ) भारत को वैश्विक OEMs के लिये 'असंबली हब' में परिणित करने में प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करती है और इसलिये इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

■ नज़ी-सरकारी सहयोग:

- जबकि भारत पछिले कुछ वर्षों से मोबाइल फ़ोन का अग्रणी नरिमाता रहा है, यह उपलब्धिकाफी हद तक नमिन प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्राप्त हुई है। अब समय आ गया है कि भारतीय वनिर्माता वैश्विक मूल्य शृंखला का अंग बनने की दशा में कार्यशील हों।
 - सार्वजनिक-नज़ी सहयोग (Public-private collaboration), सहायक नीतियाँ और कानूनी ढाँचा इस प्रगतिको आगे ले जाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- सरकार ने अगले तीन वर्षों में 10 मिलियन कुशल आईटी कार्यबल तैयार करने, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन-लकिड प्रोत्साहन नीति लागू करने आदिका लक्ष्य रखा है। ये सभी पहलें एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक वनिर्माण पारस्थितिकी तंत्र के नरिमाण की दशा में कार्य करेंगी।

■ तनाव के बीच सहयोग की तलाश:

- आज वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से कई कंपनियाँ चीन की हैं। इसके अलावा, हज़ारों चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता बाज़ार में मज़बूत उपस्थिति रखते हैं।
 - भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के कारण परस्पर सहयोग की कठिनाइयाँ बड़े पैमाने पर वनिर्माण नविश को आकर्षित करने की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमिति कर देती हैं।
- इस संदर्भ में, चीन-ताइवान के उदाहरण से सबक लिया जा सकता है, जहाँ दोनों देश युद्ध की कगार पर हैं फिर भी 4,000 से अधिक ताइवानी कंपनियाँ चीन में कार्यरत हैं। इनमें Foxconn कंपनी भी शामिल है जो चीन के सबसे बड़े नयिकताओं में से एक है।
 - राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत के प्रबुद्ध स्वार्थ में चीन के साथ व्यापार करने का रास्ता ढूँढना इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण क्षेत्र में सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

■ लचीलापन बढ़ाना:

- वर्ष 2008 में वयितनाम ने अपने FDI पर स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं को हटा दिया, जिसने सैमसंग (Samsung) को अपना वनिर्माण आधार दक्षिण कोरिया से वयितनाम स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहित किया और आज सभी सैमसंग स्मार्टफ़ोन का लगभग 60% वयितनाम में वनिर्मित होता है।
 - LG, Apple, Nintendo और कई अन्य टेक दगिगजों ने भी अपने वनिर्माण के बड़े भाग को वयितनाम में स्थानांतरित कर दिया है।
 - इसके परिणामस्वरूप, वयितनाम वर्ष 2001 में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स नरियात रैंकिंग में 47वें स्थान से ऊपर बढ़कर वर्ष 2021 में 7वें स्थान पर पहुँच गया।
- प्रतस्पर्द्धी देशों के अभ्यासों के अनुरूप कार्यबल का उपयोग कर सकने के लिये भारतीय नरिमाताओं को भी लचीलेपन के संबंध में ऐसा ही प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

नष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन अधगम (ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ऑगमेंटेड रयिलिटी (AR), वरचुअल रयिलिटी (VR) और रोबोटिक्स (Robotics) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ नए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग को बढ़ाते हुए उद्योग के स्वरूप को बदल रही हैं। भारत सॉफ्टवेयर विकास में पहले से ही एक चहिनति वैश्विक खिलाड़ी है और अपनी हार्डवेयर वनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ कर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरने की क्षमता रखता है।

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि 'आत्मनरिभर भारत' का स्वप्न तभी साकार होगा जब वनिर्माण से संबद्ध वभिन्न क्षेत्र अपनी क्षमताओं और प्रौद्योगिकी अंगीकरण के स्तर को वृहत करेंगे। समय की मांग है कि एक ऐसे वातावरण का नरिमाण किया जाए जो नवाचार को बढ़ावा दे, बौद्धिक संपदा की रक्षा करे, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करे और ऐसी आधारभूत संरचना का नरिमाण करे जो पारस्थितिकी तंत्र का समर्थन करे।

अभ्यास प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक्स ससिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में वैश्विक वनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की भारत की संभावनाओं और वदियमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

????????

प्रश्न नमिनलखिति में से कसिके अंगीकरण को प्रोत्साहति करने के लयि "R2 'व्यवहार संहति (R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसिज) साधन उपलब्ध कराती है? (2021)

- (A) इलेक्ट्रॉनिक पुनर्रचकरण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से वशि्वसनीय व्यवहार
- (B) रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि' का परस्थितिकि प्रबंधन
- (C) नमिनीकृत भूमिपर कृषिफिसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार
- (D) प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

उत्तर: (A)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/04-07-2023/print>

